



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1793]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 27, 2017/आषाढ़ 6, 1939

No. 1793]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 27, 2017/ASHADHA 6, 1939

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2017

का.आ. 2014(अ).— सेवा या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज़ के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इच्छुक फायदाग्राहियों में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन परिवार नियोजन स्कीम का प्रशासन कर रहा है, जिन्हें सम्पूर्ण देश में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा सम्पूर्ण देश में सरकारी स्वास्थ्य प्रसुविधाओं या निजी प्रत्यायित स्वास्थ्य प्रसुविधाओं द्वारा कार्यान्वित किया जाता है;

और, सशर्त नकदी सहायता (जिसे इसमें इसके पश्चात् फ़ायदा कहा गया है) निम्नलिखित स्कीमों (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) के अधीन प्रदान की जाएगी :

- (i) फ़ायदाग्राहियों और सेवा प्रदाता के लिए बंध्यीकरण के लिए वर्धित प्रतिकर स्कीम;
- (ii) फ़ायदाग्राहियों और सेवा प्रदाता के लिए प्रसवोत्तर आईयूसीडी (पीपीआईयूसीडी) प्रोत्साहन स्कीम;
- (iii) फ़ायदाग्राहियों और सेवा प्रदाता के लिए गर्भपात के उपरांत आईयूसीडी (पीएआईयूसीडी) प्रोत्साहन स्कीम;
- (iv) बच्चों के जन्म में अंतराल सुनिश्चित करने (ईएसबी) की स्कीम;
- (v) परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति स्कीम (एफपीआईएस);

और उपर्युक्त स्कीमों में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय सम्मिलित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात्:-

1. (1) स्कीमों के अधीन फायदा प्राप्त करने के पात्र किसी भी व्यक्ति से अपेक्षित होगा कि आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करने का अधिप्रमाणन करवाए।

(2) इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति, जिसके पास आधार नंबर नहीं है अथवा जिसने आधार नंबर के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है, को 30.09.2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का पात्र हो और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) पर जा सकता है।

(3) आधार (नामांकन अथवा अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, से अपेक्षित होगा कि ऐसे फायदा ग्राहियों के लिए नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित करें जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हुए हैं और यदि संबन्धित ब्लॉक या तालुक या तहसील में कोई नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है तो राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बन कर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

परन्तु फायदाग्राहियों को आधार नंबर समनुदेशित किए जाने के समय तक, स्कीम के अधीन फायदे ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित पहचान-पत्र प्रस्तुत किए जाने के अधीन प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:

- (क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या
- (ii) पैरा 2 के उप पैरा (ii) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और
- (ख) (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान-पत्र; या
- (ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थाई खाता संख्याक; या
- (iii) पासपोर्ट; या
- (iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति ; या
- (v) तहसीलदार या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा शासकीय पत्र पर जारी, ऐसे सदस्य के फोटो सहित, पहचान प्रमाणपत्र ; या
- (vi) डाक विभाग द्वारा जारी पता कार्ड, जिसमें नाम और फोटो लगा हो ; या
- (vii) बैंक फोटो पासबुक ; या
- (viii) किसान फोटो पासबुक ; या
- (ix) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कार्ड; या
- (x) राशन कार्ड ; या
- (xi) सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा जारी कर्मचारी फोटो पहचान पत्र; या

(xii) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज़ :

परन्तु और यह कि राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से पदनामित अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेज़ों की उस प्रयोजन के लिये जांच की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फ़ायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फ़ायदा प्रदान करने के लिए, स्कीम के कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक व्यवस्था करेंगे, अर्थात्:-

(1) सरकारी स्वास्थ्य प्रसुविधाओं या प्राइवेट प्रत्यायित स्वास्थ्य प्रसुविधाओं के माध्यम से मीडिया और व्यक्तिगत नोटिसों के माध्यम से फ़ायदाग्राहियों को स्कीमों के अधीन आधार की अपेक्षा के बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार किया जाएगा और उन्हें यह सलाह दी जा सकेगी कि वे अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों में 30.09.2017 तक नामांकन करवाएँ, यदि वे पहले से नामांकित नहीं हैं। स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) स्कीमों के अधीन फ़ायदाग्राहियों के आसपास, जैसे ब्लॉक या तालुका या तहसील नामांकन केन्द्रों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करेगा और फ़ायदाग्राही अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर और अन्य अपेक्षित ब्यौरे देकर राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के संबद्ध पदधारी को या सरकारी स्वास्थ्य प्रसुविधाओं या प्राइवेट प्रत्यायित स्वास्थ्य या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेबपोर्टल पर आधार नामांकन के लिए अपने अनुरोधों को रजिस्टर कर सकेंगे।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. वाई-11013/1/2016-एफ़.पी-II]

मनोज झालानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2017

S.O. 2014(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Health and Family Welfare in the Government of India is administering the **family planning Schemes under the National Health Mission**, for promotion of family planning among desirous beneficiaries, which are implemented by the State Governments and Union territory Administrations through the government health facilities or private accredited health facilities spread across the country;

And whereas, conditional cash assistance (hereinafter referred to as the benefit) is offered to the beneficiaries under the following Schemes (hereinafter referred to as the Schemes):

- (i) *Enhanced Compensation Scheme for Sterilisation for beneficiaries and service providers;*
- (ii) *Post-Partum IUCD (PPIUCD) Incentive Scheme to beneficiaries and service providers ;*
- (iii) *Post-Abortion IUCD (PAIUCD) Incentive Scheme to beneficiaries and service providers;*

(iv) *Ensuring Spacing of Births (ESB) Scheme*;

(v) *Family Planning Indemnity Scheme (FPIS)*;

And whereas, the aforesaid Schemes involve recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of the section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Health and Family Welfare hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible to receive the benefit under the Schemes is, hereby, required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
- (2) Any individual entitled to receive the benefit under the Schemes, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30.09.2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such persons may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment .
- (3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department of Health and Family Welfare which is responsible for implementation of the Schemes under National Health Mission in the State Government or Union territory Administration, is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case, there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration shall provide enrolment facilities for Aadhaar at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that, till the Aadhaar is assigned to the individual benefits under the Schemes shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

- (a) (i) If he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or
- (ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and
- (b) (i) Voter Identity card issued by the Election Commission of India; or
- (ii) Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income-tax Department; or
- (iii) Passport; or
- (iv) Driving Licence issued by the Licencing Authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
- (v) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted Officer or Tehsildar on the official letter head; or
- (vi) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts; or
- (vii) Bank Photo Passbook; or
- (viii) Kisan Photo Passbook; or
- (ix) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Card; or
- (x) Ration Card; or
- (xi) Employee Photo Identity Card issued by Government or Public Sector Undertakings; or

(xii) Any other document as specified by the State Government or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefit to beneficiaries under the Schemes, the State Government or Union territory Administration responsible for implementation of the Schemes shall make all the required arrangements including the following, namely:-

- (1) Wide publicity through media and individual notices through government health facilities or private accredited health facilities, shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Schemes and they may be advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest enrolment centres available in their areas by 30.09.2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available Aadhaar enrolment centres shall be made available to them.
- (2) In case, the beneficiaries under the Schemes are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the vicinity such as the Block or Taluka or Tehsil, the Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration shall provide enrolment facilities for Aadhaar at convenient locations and the beneficiaries may register their requests for enrolment for Aadhaar by giving their names, addresses, mobile numbers and other required details, with the concerned officials of Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration or at the government health facilities or private accredited health facilities or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F.No. Y.11013/1/2016-FP-II]
MANOJ JHALANI, Jt. Secy.